



# अधिकारों की रक्षा

## पुलिस से संबंधित अधिकार



हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

# हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण



## मुख्य संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.एस. ठाकुर  
मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

## कार्यकारी अध्यक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल  
न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

## सदस्य सचिव

श्री हरिन्द्र सिंह भनू  
(जिला एवं सत्र न्यायाधीश)

प्रकाशक :

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

एस०सी०ओ० 142-143, प्रथम तल, सैक्टर 34-ए, चण्डीगढ़।

फोन:0172-2604055, फैक्स:0172-2622875,

ई-मेल: [hslsa@chd.nic.in](mailto:hslsa@chd.nic.in), वैबसाईट: [www.hslsa.nic.in](http://www.hslsa.nic.in)

## पुलिस से संबंधित अधिकार

पुलिस से हमारा कई तरह से संपर्क होता है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिये है इसीलिये उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं। पुलिस अपने इन अधिकारों और ताकत का दुरुपयोग न करे, इसलिये यह जानना जरूरी है कि पुलिस से संबंधित हमारे अधिकार क्या हैं।

जब आप पुलिस से संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ जरूरी बातें याद रखनी चाहिए:

- हमारे देश का कानून सब पर लागू होता है।
- पुलिस हम नागरिकों और कानून की रक्षा के लिये है।
- सभी नागरिकों को, चाहे वे अमीर हों या गरीब, कमजोर हों या ताकतवर, कानूनन सुरक्षा का बराबर अधिकार है।
- पुलिस को कुछ विशेष अधिकार हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी मनमानी करें। उन्हें भी कानून के मुताबिक चलना होता है।
- कानून कहता है कि अगर पुलिस किसी से दुर्व्यवहार करती है तो उसे भी दंड दिया जा सकता है।
- यह निहायत जरूरी है कि आपको अपने अधिकारों की जानकारी हो और उनकी मांग करें। आपको अपने हक बलपूर्वक जताने चाहिए और उनका दावा करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो आपको उंचे से उंचे, बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाने से घबराना नहीं चाहिये।
- पुलिस की पूर्ण सहायता लेने के लिए, आपको भी पुलिस को पूरा सहयोग देना चाहिए। मगर कुछ बुनियादी अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 वह कानून है जिसमें भिन्न अपराध और उनकी सजा के बारे में लिखा गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 वह कानून है जिसमें लिखा है कि पुलिस और न्यायालयों को अपनी कार्यवाही कैसे करनी होगी।

## गिरफ्तारी

पिछले सप्ताह कमला अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार गयी थी। अचानक कुछ पुलिस वाले आये और उन्होंने उसे कहा कि उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई है। उन्होंने कमला को गिरफ्तार कर लिया। दो पुलिस वाले उसके हाथ पकड़ कर उसे थाने ले गये। जब उसकी सहेलियों ने उसके हाथ पकड़ कर उसे थाने ले गये। जब उसकी सहेलियों ने उसके साथ थाने जाना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया।

**गिरफ्तारी से संबंधित निम्न अधिकारों की जानकारी जरूरी है:**

- गिरफ्तारी के समय पुलिस को आपको यह बताना होगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
- यह भी बताना आवश्यक है कि आपका जुर्म क्या है।
- सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस को आपका जुर्म बताना जरूरी है।





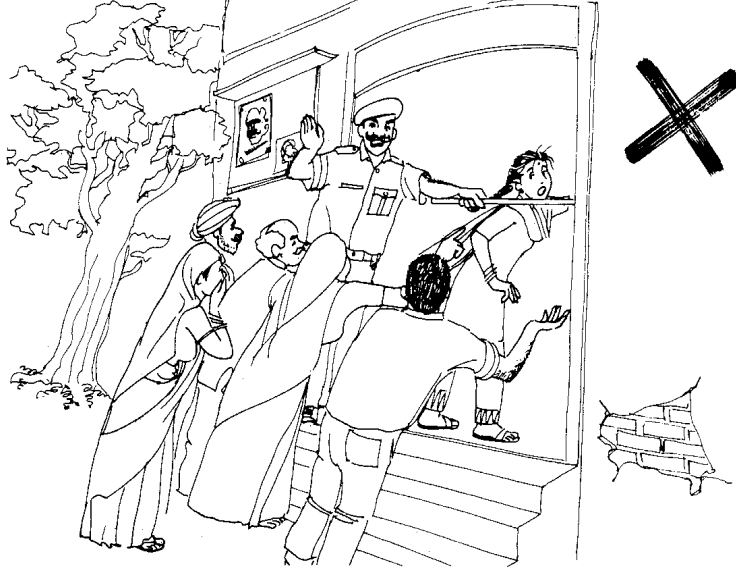
थाने ले जाने के लिये किसी को भी हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती।

- कुछ अपराधों के लिये बिना 'वारन्ट' के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है इसलिये यह जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस आपको वारन्ट दिखाये।
- आप कानूनी सहायता ले सकती हैं, जैसे कि किसी वकील को बुलाकर उसकी सलाह लेना। आमतौर से पुलिस आपकी इस मांग को मंजूरी दे देती है बशर्ते वकील को थोड़े समय में बुलाया जा सके।
- गिरफ्तारी के समय, जोर जबरदस्ती करना गैर-कानूनी है। हिरासत में लेने के लिए जितना कम से कम जोर लगता हो उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप को पुलिस हिरासत में दे दे, तो उसे हाथ लगाना भी जायज नहीं है।
- किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि पुलिस ऐसा करना जरूरी समझे, तो न्यायिक मैजिस्ट्रेट का आदेश लेना जरूरी है।
- गिरफ्तारी के समय हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। इस समय हथकड़ी लगाना गैर-कानूनी है। हथकड़की केवल उन व्यक्तियों को लगाई जा सकती है जो माने माने अपराधी हों, या जिनके भागने की घोर आशंका हो, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ मैजिस्ट्रेट को सामने पेश करने तक हथकड़ी लगाई जा सकती है। उसके बाद, हथकड़ी लगाने के लिए मैजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है।
- गिरफ्तारी के बाद तुरन्त पुलिस को मैजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी।
- गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर-अन्दर मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करना जरूरी है।
- बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है।

रमा को शनिवार को सुबह नौ बजे पुलिस ने चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया। रविवार को कोर्ट बंद रहता है। तो क्या रमा को शनिवार और रविवार दोनो दिन थाने में बंद रहना पडेगा?

नहीं, रमा की पेशी 24 घंटे के अन्दर ही होगी। शानिवार और रविवार या किसी भी त्यौहार की छुट्टी वाले दिन भी अदालत में ड्यूटी मैजिस्ट्रेट/स्पेशल मैजिस्ट्रेट बैठते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की उन्हीं के सामने पेशी होगी।

24 घंटो में पुलिस स्टेशन से अदालत पहुँचने या यात्रा में लगे समय को नहीं गिना जायेगा।



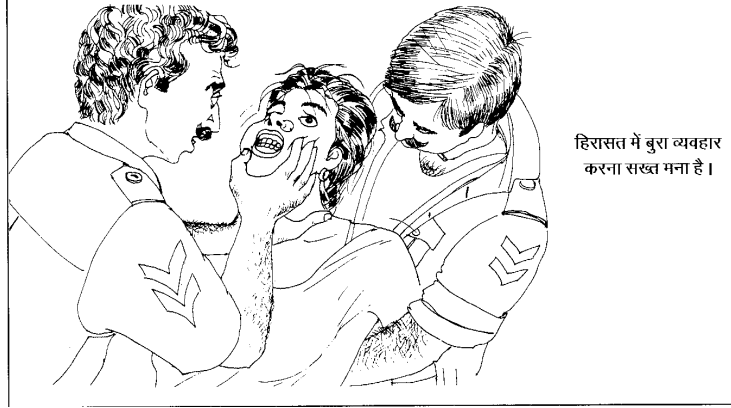
पुलिस आपके पहचानवालों या रिश्तेदारों को आपके साथ आने से नहीं रोक सकते।

### थाने में

पुलिस ने कमला को पुलिस स्टेशन के एक छोटे कमरे में धकेल कर बन्द कर दिया और जब तक उसके घरवाले वहां पहुंचे कुछ पुलिस वाले उसका बलात्कार कर चुके थे। कमला एक कोने में सहमी सी बैठी, सुबक-सुबक कर रो रही थी।

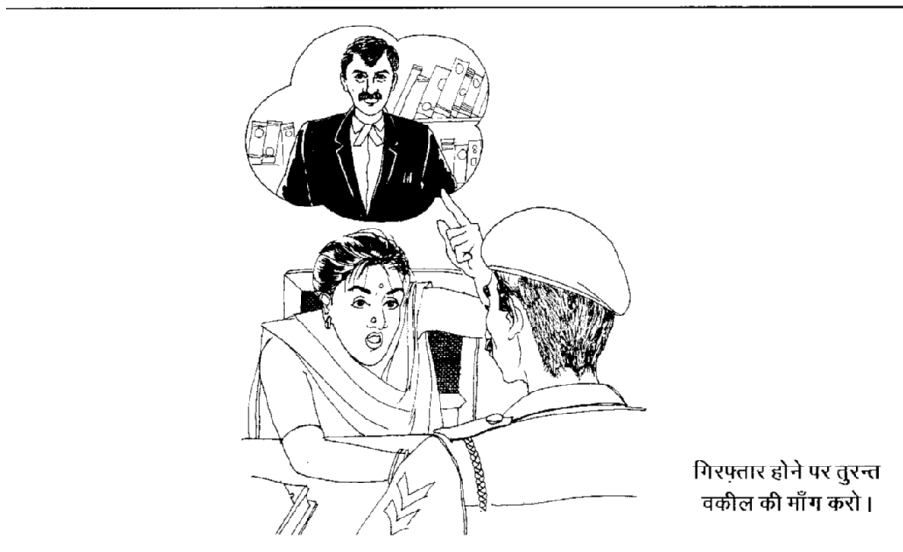
- पुलिस हिरासत में सताना, मारपीट करना या किसी अन्य तरह की यातना देना गंभीर अपराध है।
- आपकी सुरक्षा के लिये आपके पहचान वालों या रिश्तेदारों को आपके साथ पुलिस स्टेशन जाने का हक है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें साथ चलने से रोके। अगर पुलिस ऐसा करती है तो इसमें गड़बड़ की आशंका है और आपको सचेत रहना चाहिए।

अगर आपके साथ पुलिस हिरासत में बुरा-व्यवहार या मारपीट हो, तो आप मैजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं



- अगर पुलिस का कोई अधिकारी तुम्हें सताता है तो उसका नाम और हुलिया याद करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही की जा सके।
- अगर पुलिस स्टेशन पर कोई मार-पीट, बलात्कार इत्यादि हो, तो तुरन्त डॉक्टरी जांच की मांग करनी चाहिये। सरकारी डॉक्टर जांच करेगा और तुम्हें लगी चोटों की डॉक्टरी रिपोर्ट देगा। इसके बाद तुम्हें मैजिस्ट्रेट को शिकायत करनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट भी डॉक्टरी जांच का आदेश दे सकते हैं।





- तुम्हें मांग करनी चाहिये कि पुलिस स्टेशन में तुम्हें उस कमरे में रखें जहाँ स्त्रियों को रखा जाता है। अगर ऐसा कोई कमरा वहाँ नहीं है तो जिस पुलिस स्टेशन में ऐसा कमरा है वहाँ बदली की मांग करनी चाहिए।
- पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस उपस्थित रहे इस बात की माँग करनी चाहिए।

## पूछताछ

रानो एक मिल में काम करती है। कुछ दिन पहले मिल में एक चोरी हो गयी। मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और जिन व्यक्तियों पर शंका थी उनके नाम लिखवाये। उस पर पुलिस ने कुछ मजदूरों के साथ रानो को भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने रानो से जबरदस्ती कुछ कागजातों पर हस्ताक्षर करवाये। बाद में रानो को पता चला कि वे कागज जुर्म का इकरार-नामा थे। अब क्या रानो को अपराधी मानकर जेल भेजा जायेगा?

- सबसे पहले यह याद रखिये कि आप बिना पढ़े या बिना जाने किसी भी कागज पर कभी दस्तखत ना करें न ही अंगूठा लगायें। अगर आप अनपढ़ हैं तो किसी ओर से पढ़ने के लिए कहें। थाने में भी आप किसी से पढ़ने के लिए कह सकते हैं।
- पुलिस के समाने की गयी जुर्म कबूली का कोई महत्व नहीं होता। यानि उसके आधार पर आपको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।
- मैजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया गया जुर्म मान्य है। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के समाने जुर्म कबूल करने के लिए पुलिस आप पर दबाव डालती है तो आपको साफ इन्कार कर देना चाहिये और मैजिस्ट्रेट को बता देना चाहिए कि जुर्म कबूल के लिए आप पर दबाव डाला जा रहा है।

कुछ दिन पहले पुलिस का एक आदमी सुषमा के घर आया और कहने लगा कि वह किसी मामले की तहकीकात कर रहा है और उस

सिलसिले में सुषमा को पुलिस स्टेशन ले गया। कुछ दिन बाद फिर वह आधी रात के वक्त आया और सुषमा के पति को पुलिस स्टेशन ले गया। बहुत दिनों से पुलिस वाले सुषमा और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। क्या कानून ऐसे में किसी को बचा सकता है?

पुलिस को भी अपना काम कानून के कुछ नियमों के मुताबिक करना होता है। ये नियम हैं:-



- किसी भी महिला से पूछताछ सिर्फ उसके घर पर ही की जा सकती है, और कहीं नहीं। महिला पूछताछ के लिए थाने जाने से मना कर सकती है। पुरुष को भी थाने में पूछताछ के लिए सिर्फ लिखित आदेश से बुलाया जा सकता है। 15 वर्ष से कम पुरुष को भी पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता।
- पूछताछ के लिए कानूनन कोई खास वक्त नियत नहीं है। हम किसी तय वक्त पर ही पूछताछ करने के लिए नहीं कह सकते।
- परन्तु अगर हमें लगता है कि पुलिस ऐसे समय पर ही आती है, जिससे हमें परेशानी और शर्मिन्दगी हो या हमारी मर्यादा का उल्लंघन होता हो तो हम मैजिस्ट्रेट से किसी खास समय ही सवालात किये जाने की मांग कर सकते हैं।

क्या सवाल-जवाब के वक्त किसी वकील की या दोस्त की मदद ली जा सकती है?

- जी हाँ, आप अवश्य ही किसी वकील या दोस्त/रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। आमतौर पर पुलिस इसके लिये मना नहीं करती है।
- अगर आपको लगता है कि आपको किसी झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है तो जवाब देने से इन्कार कर सकते हैं।



- बाकी सारे सवालों के सच्चे जवाब देने चाहिये।
- आपसे कोई बात कहलवाने के लिये पुलिस कर्मचारी आपको कोई लालच नहीं दे सकते हैं।
- पुलिस अफसर आपको डरा-धमका नहीं सकते हैं। साथ ही वे आपको केवल सवाल या पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में या थाने (लॉक अप) में नहीं रख सकते।
- पुलिस आपसे किसी कागज पर दस्तखत या अंगूठा नहीं लगवा सकती है।

## तलाशी

एक दिन कुछ पुलिस वाले लाजो की पान की दुकान पर आये और उस पर चोरी का माल रखने का आरोप लगाया। उन्होंने उसकी दुकान की और उसके कपड़ों की भी तलाशी ली। उन्होंने दावा किया कि उन्हें तलाशी में कुछ सामान मिला। जब लाजो को कोर्ट के आगे पेश किया गया तो उसने मैजिस्ट्रेट को बताया कि पुलिस ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था। मैजिस्ट्रेट बोले, कि पुलिस ने गलत काम किया था। उन्होंने कहा:-

- सिर्फ एक महिला ही किसी महिला के शरीर की तलाशी ले सकती है। तब भी, तलाशी लेते समय महिला के साथ कोई भद्दा सुलूक नहीं होना चाहिये।



- कोई पुरुष पुलिस अधिकारी किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता। यह गैर-कानूनी है। वह पुरुष पुलिस अधिकारी को अपने शरीर की तलाशी लेने से इन्कार कर सकती हैं।

अगर कोई महिला पुलिस अफसर तलाशी के लिए उपलब्ध नहीं है, तब किसी और महिला को शरीर की तलाशी लेने के लिए कहा जा सकता है।

- पुरुष पुलिस अधिकारी आपके मकान या दुकान की तलाशी ले सकते हैं।

- तलाशी चोरी के समान, फर्जी दस्तावेज इत्यादि के लिए ही की जा सकती है। बिना कार्यवाही की तलाशी गैरकानूनी है।
- तलाशी के लिये मैजिस्ट्रेट वारन्ट की आवश्यकता होती है।
- किसी भी तलाशी और बरामदी के वक्त आसपास रहने किन्ही दो अपक्षपाती और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को होना जरूरी है।
- तलाशी का पंचनामा बनाना जरूरी है। अगर कोई वस्तु जब्त की जा रही है तो उसके बारे में पंचनामों में लिखा होना चाहिये। इस पंचनामों पर उन दो प्रतिनिष्ठ व्यक्तियों के दस्तखत होने जरूरी हैं जो तलाशी के वक्त मौजूद थे। इस पंचनामे की एक प्रति आपको दी जानी चाहिए।
- तलाशी लेने वाले की भी तलाशी ली जा सकती है।

## कोर्ट में

जब किसी अपराध के मामले में आपकी सुनवाई हो रही हो तो याद रखिये:

- आपको वकील की सहायता लेने का अधिकार है। तुरन्त किसी वकील की सहायता लीजिये।
- अगर कोई गरीब है और वकील की फीस नहीं दे सकता तो उसे मुफ्त कानूनी सलाह मिलने का हक है। कोर्ट खुद वकील नियुक्त करेगी। इस व्यक्ति के कोर्ट या वकील को कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। उसका मामला सरकारी खर्चे पर लड़ा जायेगा।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है:

- पुलिस आरोप-पत्र पेश करेगी।
- आरोप (चार्ज) लगाए जाएँगे। यानि कि वह अपराध तय किया जाएगा जिसके लिए आपका केस चलेगा।
- अपराध के संबंध में साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किए जाएँगे। उसके बाद आरोपी अपने बचाव में सारी चीजें प्रस्तुत करेगा।
- इनके आधार पर कोर्ट अपना निर्णय देगा।
- अगर कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचता है कि अपराधी ने अपराध किया है तो कोर्ट सजा सुनाएगी जो कि कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।



लड़की से छेड़खानी करना  
अपराध है। पुलिस में जरूर  
रिपोर्ट लिखवाईये।

## जमानत

कुछ समय पहले यह सुनने में आया था कि हमारे गांव में अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ दिया गया है।

### जमानत क्या है?

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपराध की सुनवाई के दौरान कार्यवाही के लिए उपस्थित रहने की शर्त पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति खुद या उसकी ओर से कोई और जिम्मेदारी लेते हैं। इसी को जमानत कहते हैं।

अपराध दो प्रकार के होते हैं: जमानती और अजमानती। जमानती अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार होता है। अजमानती अपराध में मैजिस्ट्रेट के आदेश पर ही छोड़ा जा सकता है।

गिरफ्तार करते वक्त पुलिस को यह बताना होगा कि उस जुर्म के लिये पुलिस आपको जमानत पर छोड़ सकती है या जमानत के लिए मैजिस्ट्रेट का आदेश जरूरी है। पुलिस खुद यह जानकारी नहीं देती है तो तुम्हें पूछकर इसका पता लगाना चाहिये।

**याद रखिये** - जिस जुर्म में जमानत पर छोड़ने की व्यवस्था है उसके लिये आपको जमानत मिलना आपका अधिकार है। हाँ, जमानत के लिये जमानत जमानत पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही किसी व्यक्ति की जमानत भी लगेगी। मतलब यह है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जिसके लिए पुलिस आपकी जमानत नामंजूर नहीं कर सकती।

जमानत पर छूटने का मतलब बरी होना नहीं है। जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को बहकाने, डराने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर जमानत रद्द की जा सकती है और आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है।

कौन से जुर्म जमानती हैं और कौन से अजमानती यह सूची कानून में ही दी गई है, पुलिस या कोर्ट की मर्जी पर निर्भर नहीं है।

## जमानत की अर्जी में क्या लिखना होगा?

अर्जी में निम्नलिखित बातें लिखनी होंगी:

- आपका नाम:
- आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है:
- आपको किस तारीख को गिरफ्तार किया गया है:
- आपका पता, आप वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं और आपके परिवार का संक्षिप्त विवरण:
- यह मकान आपका है/आपके पिता का है या फिर किराए का है:
- यदि मकान किराए का है तो मकान मालिक का संक्षिप्त विवरण:
- आप कहाँ काम करते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं उसका संक्षिप्त विवरण:
- आपको इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है-तभी लिखें जब यह सच हो:- लिखें कि आपने यह गुनाह नहीं किया है-तभी लिखें जब यह सच हो:
- लिखें कि 'मैं यह वादा करता हूँ कि मैं भागूँगा नहीं/गवाहों को गुमराह नहीं करूँगा/सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं करूँगा/और जब भी जरूरत पड़े अदालत या पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाऊँगा।'
- मेरी यह प्रार्थना है कि मुझे जमानत पर रिहा किया जाएँ।
- अपने बारे में कोई और जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं जैसे मैं ..... जगह/समुदाय का रहने वाला हूँ। ..... समुदाय/जगह के लोग मुझे जानते हैं और इसलिए मेरे भाग जाने की आशंका नहीं होनी चाहिए।

- यह अर्जी आपकी अदालत में पहली पेशी के दिन जज साहब को दी जा सकती है।
- जमानत की अर्जी एक सादे कागज पर भी दी जा सकती है।

**अग्रिम जमानत:** जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है यानि कि गिरफ्तारी की स्थिति में उसको तुरन्त जमानत पर छोड़ दिया जाए।

### जमानत कैसे होती है?

#### जमानती अपराध

- जिस जुर्म में पुलिस अपराधी को जमानत पर छोड़ सकती है उसे जमानती जुर्म कहते हैं। ऐसे में अपराधी अपने रिश्तेदार या पहचान के किसी व्यक्ति से कहकर उसके द्वारा जमानत देने पर छूट सकता है। जमानत किसी भारी रकम की नहीं होती। कुछ रूपयों की जमानत देकर आपको छोड़ दिया जायेगा।
- जमानत का तरीका बहुत ही सरल है इसके लिये आपको किसी वकील की मदद की भी जरूरत नहीं है। पुलिस आपको एक फार्म (आवेदन पत्र) देगी। आप इसे भरकर उन्हें दे दीजिये। अगर आपको पढ़ना-लिखना नहीं आता हो तो अपनक किसी पहचान वाले से फार्म को भरवा लीजिये। आप चाहें तो पुलिस वालों से भी उसे भरवा सकती हैं।
- इसके अलावा एक या दो व्यक्ति भी जमानत देंगे। जमानत पत्र में यह लिखा होगा कि जरूरत होने पर तुम पुलिस या कोर्ट में हाजिर रहोगे, इसकी जिम्मेदारी उन पर है।
- जमानत करते समय कुछ पैसे नकद नहीं दिये जाते। हाँ, अगर आरोपी कार्यवाही में शामिल न हो या भाग जाए, तो उसकी जमानत देने वालों को जमानत पत्र में लिखा पैसा भरना पड़ेगा।

- जमानती जुर्म में जमानत होने पर पुलिस को आपको तुरन्त छोड़ना पड़ेगा। यह आपका अधिकार है।



कुछ अपराधों के लिये जमानत  
मिलना आपका अधिकार है।

## जमानत-पत्र

जमानत-पत्र का एक फार्म होता है। उसमें निम्न बातें लिखनी होंगी:-

- आपका नाम
- आपका पता
- थाने या कोर्ट का नाम
- जमानत की रकम
- जमानत की शर्तें (जैसे, किसी भी दिन बुलाये जाने पर उस थाने या कोर्ट में हाजिर होने के लिए वचनबद्ध होना)

उसमें यह भी लिखा जायेगा कि जमानत की शर्तें यदि तोड़ी गई, तो सरकार के पक्ष में जमानत की रकम जब्त कर ली जाये।

जमानत की शर्तें तोड़ने पर, जमानत लेने वाले को एक सूचना दी जायेगी कि जमानत की रकम जमा करवा दे। उस पर भी यदि वह नहीं देता, तो जमानत की रकम उसकी सम्पत्ति में से जब्त करने का वारन्ट निकाला जायेगा। जमानत की शर्तें तोड़ने पर आरोपी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

### अजमानती अपराध

- अगर पुलिस कहती है सिर्फ मैजिस्ट्रेट की आपको जमानत पर छोड़ने का आदेश दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जुर्म जमानती जुर्म नहीं है। आपको हक के तौर पर जमानत नहीं मिल सकती। तब जमानत पर छूटने के लिए आपको मैजिस्ट्रेट को अर्जी देनी होगी। आपके जुर्म को देखकर मैजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़ने या न छोड़ने का आदेश देंगे।

यदि आरोपी मुकदमा चलने की अवधि में अपने आरोपित अपराध के लिए दी गई सजा का आधा समय हिरासत में काट चुका हो तो उसे

निजी बाण्ड पर छोड़ना आवश्यक है। यह प्रावधान मृत्यु दण्ड दिए जाने वाले अपराधों पर लागू नहीं होता।

## अपराधों की रिपोर्ट

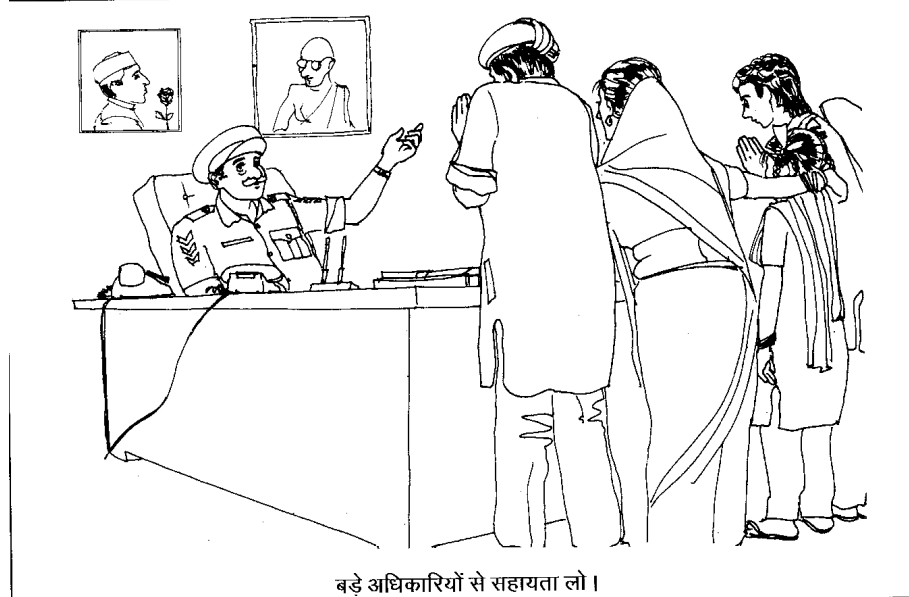
हम लोग गांव में रहते हैं। यहाँ के जमींदार और दूसरे 'बड़े लोग' हमें हमेशा तंग करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हमारी बेटी बसन्ती स्कूल से घर आ रही थी। तब जमींदार के यहां काम करने वाले लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी की। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए?

किसी के साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार करना अपराध है। हर कोई जानता है कि लड़कियों या महिलाओं के साथ छेड़खानी या उन्हें तंग करना भी अपराध है। अगर आपके साथ ऐसा जुर्म हुआ है तो आप तुरन्त पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवायें। बेहतर होगा अगर रिपोर्ट लिखवाते समय आप किसी रिश्तेदार या जान-पहचान वाले किसी व्यक्ति को साथ ले जायें। रिपोर्ट लिखवाने अकेले भी जा सकते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए किसी के साथ जाना ठीक रहता है।

### रिपोर्ट क्या है?

रिपोर्ट का मतलब है कि आप पुलिस को जाकर बतायें कि कोई अपराध किया गया है। इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या 'एफ.आई.आर.' (FIRST INFORMATION REPORT) कहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू करेगी।





- जब बसन्ती अपने माँ-बाप के साथ पुलिस में छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने गयी तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दिया क्योंकि जिन लड़कों ने छेड़खानी की थी वे पुलिस वाले की पहचान के थे। ऐसे में क्या करना चाहिये?
- यदि पुलिस रिपोर्ट न लिखे, तो अपनी शिकायत लिख कर पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) को डाक द्वारा भेजनी होगी। चिट्ठी पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए।
- वे इस शिकायत की जाँच करेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि कोई अपराध हुआ है तो वे थानेदार को रिपोर्ट लिखने का आदेश देंगे या स्वयं उसकी जाँच करेंगे।
- अगर मामला गंभीर है और तुरन्त कार्यवाही की जरूरत है तो आप एस.पी./डी.एस.पी. इत्यादि जैसे वरिष्ठ अधिकारियों से मिल भी सकते हैं। मिलने पर भी लिखित आवेदन जरूर दें।

- अगर पुलिस के बड़े अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आप घटना की विस्तृत जानकारी लिखकर मैजिस्ट्रेट को दीजिये।
- मैजिस्ट्रेट जाँच अधिकारी को छानबीन का आदेश देंगे। वे खुद भी जाँच कर सकते हैं।

एक बार सुनीता अपने माँ-बाप के साथ पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गयी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह मैजिस्ट्रेट के पास जाकर उन्हें घटना की जानकारी दे। ऐसा क्यों?

जब सुनीता ने सारी घटना पुलिस को बतायी तो पुलिस ने जाना कि सुनीता जिस शिकायत को लेकर आयी है वह असंज्ञेय अपराध है।

असंज्ञेय अपराध की तरह के निजी विवाद है जिनसे आम जनता का कोई सरोकर नहीं होता। जैसे बदनामी करना, गर्भवती होने पर नौकरी से निकाल दिया जाना, किसी को मामूली चोट पहुँचाना आदि।

पुलिस को असंज्ञेय मामलों की जाँच का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर मैजिस्ट्रेट उन्हें जाँच का आदेश दें तब अवश्य ही पुलिस जाँच कर सकती है।

**क्या सुनीता सीधे मैजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत कर सकती है?**

- हाँ, सुनीता मैजिस्ट्रेट के पास जाकर जुबानी या लिखित शिकायत दे सकती है।
- अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि सुनीता के साथ असंज्ञेय अपराध हुआ है तो वह पुलिस को जाँच करने का आदेश देंगे।
- ऐसे मामलों को छोड़कर बाकी सारे मामलों में पुलिस को रिपोर्ट लिखनी होगी।

**अपराध की रिपोर्ट कैसे लिखवाई जाती है?**

- रिपोर्ट मुँह जबानी या लिखित हो सकती है।

- आपकी रिपोर्ट में सारी आवश्यकता जानकारी होनी चाहिये। मतलब आपका नाम, पता, अपराधी का नाम-पता (अगर मालूम हो तो), उसका हुलिया, क्या अपराध हुआ है उसकी जानकारी, अपराध कैसे और कहाँ हुआ है उसकी जानकारी।
- अगर अपर रिपोर्ट नहीं लिख सकते हैं तो जुबानी सारी घटना पुलिस को बतायें। पुलिस उसे लिखकर आपको पढ़कर सुनाएगी। अगर आपको लगता है कि शिकायत ठीक लिखी है तो आप अपने दस्तखत या अंगूठा उस पर लगायें। परन्तु अगर आपको लगता है कि रिपोर्ट ठीक नहीं लिखी है तो आप उसे ठीक करवायें। फिर दस्तखत करें। जब कोई रिपोर्ट पुलिस लिखती है, उसे एफ.आई.आर. कहते हैं।
- गलत एफ.आई.आर. पर दस्तखत नहीं करना चाहिए।



- पुलिस को चाहिए कि वह आपको रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) की एक प्रति अवश्य दे। यह आपका हक है। एफ.आई.आर. की कॉपी आपको मुफ्त दी जाएगी। कॉपी एफ.आई.आर. तर्ज होने के समय तुरन्त दी जानी चाहिए।

- वैसे आपको रिपोर्ट लिखवाते समय किसी गवाह की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, वह कोई 'बड़ा आदमी' है या उसकी पुलिस में पहचान है और उस वजह से पुलिस आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकती है तो अपनी सुरक्षा के लिये आप अपने साथ अवश्य ही किसी जान-पहचान के व्यक्ति को ले जायें।

### रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) कब दर्ज करायें?

- घटना के बाद तुरन्त रिपोर्ट लिखवायें, यह आवश्यक है। यह इसीलिये, कि सबूत मिलने में और अपराधी को पकड़ने में आसानी होती है।
- अगर आपको अपराधी का नाम, पता आदि मालूम है तो यह जानकारी 'एफ.आई.आर.' (रिपोर्ट) दर्ज कराते समय ही पुलिस को दें।
- अगर किसी कारण से रिपोर्ट लिखवाने में आपसे देरी होती है तो उस कारण को भी रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में लिखवायें, यह भी जरूरी है।

### एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कितना खर्च होता है?

- एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। सरकार इसका खर्च उठाती है। अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पैसे माँगता है, तो वह रिश्वत है और इस बात को लिखित रूप में उच्च अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

### अपराध की शिकायत कहाँ करनी चाहिए?

- अपराध की शिकायत घटना-स्थल से नजदीकी पुलिस थाने में की जानी चाहिए। अगर पुलिस को लगता है कि अपराध किसी और थाने के अन्तर्गत आता है, तब भी उन्हें एफ.आई.आर. दर्ज करना पड़ेगा और फिर उसे सही थाने में अंतरण करनी होगी। इसके लिए यह 'शून्य' एफ.आई.आर. दर्ज करते हैं और फिर उसे सही थाने में भेज देते हैं।

## रिमांड

किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जब मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो मैजिस्ट्रेट तीन चीज़े कर सकता है।

1. जमानत पर छोड़ दे।
2. पुलिस हिरासत में भेज दे।
3. न्यायिक हिरासत में भेज दे।

रिमांड का मतलब है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेजना।

**पुलिस हिरासत:** किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने के वक्त पुलिस उसकी हिरासत माँग सकती है ताकि वह पूछताछ जारी रख सके। कोर्ट लिखित आदेश से यह स्वीकार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति को फिर पुलिस थाने ले जाया जाएगा। किसी व्यक्ति को कुल 15 दिनों से ज्यादा पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। पुलिस रिमांड के दौरान किसी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार, मारपीट इत्यादि, गैरकानून है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस बात की शिकायत मैजिस्ट्रेट से दोबारा पेश किए जाने पर अवश्य करें।

**न्यायिक हिरासत :** इसे 'जे.सी.' (जुडिशियल कस्टडी) भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आरोपी को कोर्ट के संरक्षण में, जेल में रखा जाएगा और वहा कार्यवाही के लिए वहीं से पेश होगा। न्यायिक हिरासत एक समय पर केवल 15 दिन के लिए हो सकती है। यानि हर 15 दिन हिरासत में रहने के बाद बंदी को फिर मैजिस्ट्रेट के सामने बंदी को शारीरिक रूप से पेश करना आवश्यक है। केवल कोर्ट के लॉक अप तक ले जाना काफी नहीं। बिना जज के सामने पेश किए हिरासत की अवधि बढ़ानी गैर कानूनी है।

**क्या अपराध की कार्यवाही चलने तक पूरे समय आरोपी को जेल में रहना पड़ेगा?**

यदि आरोपी की जमानत न हो तो उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। हाँ, आरोपी चाहे तो बार-बार जमानत की अर्जी लगा सकता है। हर आरोपी को जल्द मामले के निपटारों का अधिकार है। इसीलिए कानून में यह प्रावधान है कि यदि जाँच एक समय सीमा में नहीं खत्म की जाती, तो आरोपी को जमानत पर छूटने का हक है।

**यह समय सीमा क्या है?**

जिन अपराधों की सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल का कारावास है, उनमें जाँच/आरोप पत्र 90 दिन के अन्दर न होने से आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है। बाकी अपराधों के लिए, जाँच/आरोप पत्र 60 दिन के अन्दर पूरी न होने से आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

## डी.के.बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

(1997 1 SCC 416)

पुलिस की हिरासत में होने वाली यातनाओं में लगातार वृद्धि को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तारी, पूछताछ एवं समय में बरती जाने वाली सावधानियों के लिए कुछ निर्देश दिये हैं:-

### गिरफ्तारी और पूछताछ के समय

- सभी पुलिस कर्मचारी एक पट्टी लगाएंगे जिस पर उनका नाम एवं पद स्पष्ट रूप से लिखा हो
- जो पुलिस अधिकारी पूछताछ में शामिल है उनका ब्यौरा, रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए।

### गिरफ्तारी पर्चा (मैमो ऑफ अरेस्ट)

- गिरफ्तारी करते समय पुलिस एक गिरफ्तारी पर्चा बनाएगी।
- इस पर्चे पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होंगे। यह गवाह गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो सकता है अथवा उस क्षेत्र को कोई जाना-माना व्यक्ति भी हो सकता है।
- इस पर्चे पर गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर, होने चाहिए।
- इस पर्चे पर गिरफ्तारी का समय और तारीख दर्ज होनी चाहिए।

### निरीक्षण पर्चा (इन्स्पैक्शन मैमो)

- गिरफ्तार व्यक्ति के बदन पर साधारण अथवा गम्भीर चोटों की जाँच होनी चाहिए।

- यदि चोट हो तो वह निरीक्षण पर्चे पर दर्ज होनी चाहिए।
- निरीक्षण पर्चे पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी, दोनों के हस्ताक्षर होंगे।
- इस निरीक्षण पर्चे की एक कॉपी गिरफ्तार व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

**आपका यह अधिकार की आपकी गिरफ्तार एवं निरोध की सूचना किसी को दी जाये।**

- गिरफ्तार व्यक्ति यह अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी या निरोध की सूचना उसके रिश्तेदार, अथवा किसी मित्र को दी जाये।
- गिरफ्तार करके रखे जाने वाले स्थान के बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाये।
- अगर वह मित्र या रिश्तेदार किसी अन्य जिले या शहर में रहते हैं तो वहाँ के थाने को तार के माध्यम से गिरफ्तारी के 8-12 घंटे के अन्दर सूचना दी जानी चाहिए।
- यह सूचना उस जिले के कानूनी सलाह केन्द्र के माध्यम से भी दी जा सकती है।

**थाने में रोजनामचा (डायरी)**

- रोजनामचा में गिरफ्तारी के तथ्य दर्ज होने चाहिए।
- उसमें जिस मित्र को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी है, उसका नाम और पता भी दर्ज होना चाहिए।
- जिस पुलिस अधिकारी की हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया हो उस पुलिस अधिकारी का नाम व अन्य विवरण दर्ज होनी चाहिए।

### **डॉक्टरी जांच का अधिकार**

- गिरफ्तार व्यक्ति की डॉक्टरी जांच गिरफ्तारी के उपरान्त हर 48 घंटे के बाद एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा करवाई जाये।
- जांच करने वाला डॉक्टर उस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा संचालक द्वारा चुने गये पैनल का सदस्य होना चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा संचालक इस तरह ही पैनल सभी तहसीलों एवं जिला मुख्यालयों के लिए तैयार करनी चाहिए।

### **कानूनी सहायता का अधिकार**

- गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

### **इलाका मैजिस्ट्रेट**

- गिरफ्तारी से संबंधित सभी कागजों की एक नकल इलाका मैजिस्ट्रेट के लिए भेजनी होगी।
- इसमें गिरफ्तारी पर्चा भी शामिल है।

### **पुलिस कंट्रोल रूम**

- सभी जिलो व राज्य मुख्यालयों पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किये जाने चाहिए।
- पुलिस का यह कर्तव्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को रखने के स्थान की सूचना कंट्रोल रूम को भेजे।
- यह सूचना गिरफ्तार के 12 घंटे के अन्दर इस कंट्रोल रूम को भेजनी चाहिए।
- यह जानकारी कंट्रोल रूम में ऐसे नोटिस बोर्ड पर साफ शब्दों में लगाई जाने चाहिए जिस पर आसानी से नजर पड़े।

## हिरासत के दौरान हुई मृत्यु में मानव आयोग द्वारा दिये गये निर्देश

1. आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार यदि पुलिस हिरासत या जेल में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर आयोग को भेजी जानी चाहिए। अगर ये सूचना इस दौरान नहीं दी जाए तो आयोग यह मानकर चलेगा कि प्राधिकारी इस मृत्यु से जुड़े तथ्यों को छपाने की कोशिश कर रहा है।
2. ये सुनिश्चित करने के लिए कि मृत्यु की सूचना तुरन्त और सही दी गई है, आयोग ने राज्यों को ये निर्देश दिये है कि शव परीक्षण की विडियो फिल्म उतारी जायेगी और उसे आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
3. आयोग ने यह निर्देश दिए है कि हर राज्य के पुलिस मुख्यालय में मानव अधिकार सेल बनाये जाएँ।
4. आयोग ने राज्य सरकार को मुफ्त दूरभाष सेवा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव दिया है। यह सूचना लिखते समय सूचना देने वाले को जबरदस्ती अपना नाम व पता बताने को न कहा जाए।

हिरासत में हिंसा व मृत्यु के मामलों को सीधे राज्य के उच्च न्यायालय में एक यचिका द्वारा ले जाया जाए। हिरासत में हिंसा के शिकार हुए लोगों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।

### हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य

मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय	मुख्य संरक्षक
न्यायाधीश, पंजाब एवम् हरियाणा उच्च न्यायालय	कार्यकारी अध्यक्ष
सचिव, न्याय प्रशासन विभाग, हरियाणा	सदस्य
सचिव, वित्त विभाग, हरियाणा	सदस्य
सचिव, विधि तथा विधायी विभाग, हरियाणा	सदस्य
महाधिवक्ता, हरियाणा	सदस्य
महानिदेशक, पुलिस विभाग, हरियाणा	सदस्य
अध्यक्ष, बार कौंसिल, हरियाणा	सदस्य
निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा	सदस्य
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला	सदस्य
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार	सदस्य
अध्यक्षा, हरियाणा राज्य महिला आयोग	सदस्य
निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा	सदस्य
अध्यक्ष, विधि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	सदस्य
सदस्य सचिव	